[Shri Pragada Kotaiah]

The Minister of State for Public Grievances has in a letter informed me three months back that the Government of Andhra Pradesh would hold elections to our mills, but nothing has happened in this respect.

I urge upon the Ministry of Textiles headed by a dynamic and dedicated Minister that funds be provided for weavers' cooperative spinning mills and also immediate steps should be taken to reopen the mills. Arrangements should be made to hold elections to the mills so that an elected management may run the mills to the advantage of the workers and weavers. This would avoid untoward incidents in the area and the workers and the weavers will feel happy when the mills work successfully.

**Need to set up statutory developmet Boards to Develop Vidarbha, Marathwada, and Konkan Areas**

**डा० बापू कालदाते** : (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, आप भी बैठी हैं, श्रीमान साल्वे जी यहां पर हैं, जगेश भाई भी यहां पर हैं। बहुत सालों से जिस सवाल का जिक्र मैं इस सदन में करता आया हुं उसी सवाल के बारे में फिर से मुझे कहने की नौबत आ गई है। आप सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में 1985 में महाराष्ट्र विधान मण्डल ने यह प्रस्ताव किया कि संविधान की धारा 371(2) के तहत महाराष्ट्र के जो पिछड़े हुए इलाके हैं जैसे विदर्भ, मराठवाड़ा, इनके लिए एक वैधानिक मंडल की नियुक्ति की जाए। 1985 से लेकर मैंने बार बार इस बात को कहा है। एक सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने इस बात का जिक्र न किया हो कि इसको जल्दी बनाना अति आवश्यक है।

मैं अगर आपको कहूं, 20 दिसम्बर, 1990 को टाइम्स आफ इंडिया ने एक आलेख लिखा था, जिसमें यह बात कही गई है कि जिले इज डेंजरस इन फार्मेशन आफ दी बोर्डस। यह इसके कारण डेंजरस है, जैसा कि मैंने कहा था कि 1960 में तो संयुक्त महाराष्ट्र बन गया, लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र से एक एकात्म महाराष्ट्र बनाने के लिए जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए इलाके हैं, जैसे विदर्भ है, मराठवाड़ा है, क्योंकि विदर्भ मध्य भारत से आय मराठवाड़ा हैदरावाद की रियासत से आया और यह समझ कर आया कि एक-भाषिक राज्य जब बनेगा, तब हमारा जो आर्थिक पिछड़ापन है, वह कम करने में हम जैसे सांस्कृतिक दृष्टि से एक हो जायेंगे भाषा के आधार पर, वैसे ही हम आर्थिक एकदृष्टा हो जायेंगे अगर हमारी प्रगति की गति ज्यादा तीव्र होगी और ज्यादा सजगता से सरकार देखेगी।

यह भी बात उस समय के जो मुख्य मंत्री थे, श्री वाईबी० चव्हाण, उन्होंने कही थी कि मैं यह देख लूंगा कि भले ही मैं आपको गाज निश्चित रूप से नहीं कह सकूंगा, लेकिन इस बात को मान्य करता हूं कि यह पिछड़े हुए ऐसे उभर आयें कि जिससे यह एकात्म महाराष्ट्र बन जाए। अब कितने साल तक हम इस बात को कहते रहें। यह जो अपनी केंद्रीय सरकार है, यह जो हम को जवाब देती है-- हर समय जब मैं जवाल उठाता हूं, तो सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है। मेरे पास इनके तीन जवाब रखे हैं, पर इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मेरे पास एक जवाब है 19 मई, 1992 का, दूसरा जवाब है 9 दिसम्बर, 1992 का और तीसरा जवाब है 31 मार्च, 1993 का। तीनों वही जवाब--अगर आप पढ़ेंगे, तो सेम थिंग--

The various legal and constitutional implications are being examined.

दूसरा है--

The matter is still under examination from legal, constitutional and political angles.

शब्द इधर का उधर हो जाता है, लेकिन मतलब वही रहता है। लेकिन लास्ट में उन्होंने जो एक बात लिखी है, वह मुझे समझ में नहीं आ रही है। आखिर में

31 मार्च, 1993 का जो जवाब है, उसमें उन्होंने लिखा है--

The proposal has to be examined from legal, constitutional, political and Administrative angles as complex issues are involved.

I don't think any political issue is involved in it

क्योंकि अभी हाल ही में--आप भी शायद उस सभा में मौजूद थीं--हाल ही में जो संसद सदस्यों की बैठक आज के मुख्य मंत्री जी ने बुलाई थी, उसमें हमने पूछा था कि केंद्रीय सरकार तो हमको बराबर ऐसा ही जवाब दे रही है । आपकी क्या राय है । महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा है कि हमने साफ तौर पर केंद्रीय सरकार को कह दिया है कि जो फार्मुलेशन आप तैयार करेंगे, उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं । हम इस फार्मुलेशन के तहत अगर स्टैट्युरी बोर्टस का निर्माण हो जाता है, तो हम तुरंत उसको अमल में लाने के लिए प्रयास करेंगे । मैंने इसका भी जिक्र किया है कि गोविंद भाई के सत्कार समारोह में प्रधान मंत्री जी आये थे और जब यह सवाल उनको पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा कि मैं यह स्टैट्यूटरी डिवलपमेंट बोर्ड--"लोकरात लौकर स्थापित करीन" यह मराठी में कहा था । लौकरात लौकप के माने जल्दी से जल्दी ।

उसको भी दो साल हो गये । अब जल्दी से जल्दी कितनी देर तक--यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है ।

तो हम आपके माध्यम से फिर एक बार कहते हैं कि जनता में जो असंतोष है, जनता में अपने विकास की जो आंकाक्षायें हैं, जनता खुद एक एकात्म महाराष्ट्र, समतल स्तर का महाराष्ट्र बनाना चाहती है । उसकी आशाओं में अगर आप रुकावट लाते रहेंगे, तो इन विभागों में जो असंतोष फैल रहा है, वह असंतोष सरकार काबू नहीं कर पायेगी । जो झारखंड में हुआ, जो यहां बोड़ो लैंड के लोग कर रहे हैं, अगर वही रास्ता अपनाना है, तो बोल दीजिए कि हम नहीं करना चाहते हैं । तो फिर लोग जो करना है, सो करेंगे । लेकिन मैं यह चाहता हूं --(**समय की घंटी**) कि लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोकतंत्र की सरकार लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिसाद करें । अगर लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिसाद सरकार नहीं करेगी, तो लोग जो मन में आया, करने के लिए तैयार, बाध्य हो जाते हैं ।

इसकी जिम्मेदारी लोगों पर नहीं होती है, सरकार पर होती है कि जो उसका प्रतिसाद नहीं देती है । साल्वे जी यहां बैठे हैं । हम तो उनको ही कहेंगे--हम तो मानते हैं कि आप इधर के प्रतिनिधि होने के नाते सरकार में गये हैं । वहां भी कैबिनेट में, तो हमारी यह आपसे भी मांग है और आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है कि जो पिछड़े इलाके हैं, उनका प्रतिनिधित्व आप करें और महाराष्ट्र के विकास की प्रक्रिया को समतल दृष्टि से और प्रभावी रूप से आगे लाने का प्रयास करें । मैं आपके माध्यम से उनको इतनी प्रार्थना करता हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have two more Special Mentions. ... (*Interruptions*) ...

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam Deputy Chairperson, I totally support Dr. Bapu Kaldate's Special Mention. Madam, you are there.

**डा० बापू कालदाते** : मैडम भी करेंगी । ...(**व्यवधान**)

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : (उत्तर प्रदेश) : मैं तो महाराष्ट्र का नहीं हूं, लेकिन जो कुछ विदर्भ के साथ हुआ वह ठीक नहीं हुआ । वास्तव में तो विदर्भ एक अलग प्रांत बनने की स्थिति में था, लेकिन खैर रीजन सेक आपने उसको एक अलग प्रान्त न बना करके महाराष्ट्र में मिलाया है । लेकिन बम्बई और मध्य भारत इतना अलग क्षेत्र है, मैं बम्बई का कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां की लोल-चाल , रिहाइश बिल्कुल अलग है । तो कम से कम इन के साथ यह अन्याय न हो इसलिए इनको डिवैलपमेंट बोर्ड बना दें, जो कंस्टीट्यूशन में प्रोवाइडिड है तो सैपेशट होने के बावजूद भी मेरी सिंपैथी और मेरी पार्टी की सिंपैथी इन के साथ है । ...(**व्यवधान**)

डा० बापू कालदाते : साल्वे जी, आप कहिए । आप जरुर कहिए । . . . (व्यवधान) . . . आपने एक बार नहीं, दो बार हमारे साथ सदन में बोला है । (व्यवधान) . . . इस इश्यू के पक्ष में आपने दो बार यहां भाषण किया है । आप कहिए । . . . (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Salve Saheb should say where it is. His word will have some say. . . (*Interruptions*) He will say at the right place.

डा० बापू कालदाते : हम कहते हैं आपने कहा है । हमको याद है . . . (व्यवधान) . . . खामोशी से सवाल नहीं हल हो रहा है । हम कहते हैं आपने कहा है । हमें याद है उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कहा है । हम यह चाहते हैं कि . . . (व्यवधान)

SHRI JAGESH DESAI: He is doing his best.

THE MINISTER OF POWER (SHRI N. K. P. SALVE): At the moment I am doing my roster duty, Madam.

उपसभापति : साल्वे जी, आप जहां जरुरत है वहां आप कहिएगा । . . . (व्यवधान)

I know. Wherever the Members want you to the youd influence, use it at the right place.

Let us finish the special mentions now.

Shri Arangil.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Whatever Maharashtra wants, is gets, I know that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will cut down the time. Two minutes, yes.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN (Kerala): I shall be very brief because I am feeling hungry.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So am I. I Will be very happy.

**Closure of Aralm Agriculture farm owned by the State farms Corporation of India in Cannanor District in Kerala**

SHRI ARANGIL SHREEDHARAN (Kerala): Madam, I want to make this special mention about the pathetic situation in the Aralam Agricultural Farm in the Cannanor District of Kerala. It is a unit of the Farms Corporation of India. This is one of the most prosperous farms where collective agriculture has succeeded. We have been experimenting with co-operative agriculture and collective agriculture. At several places the farms have failed, but this Farm has succeeded to a very considerable extent. The Farm came into existence in 1970 with a capital investment of Rs. 15 crores. By sincere dedication of the workers and the management, the capital was raised to the tune of Rs. 120 crores.

Now the Farm has been closed consequent on a strike by the workers. Their demands are very legitimate and very moderate. I shall enumerate them for the information of the Government. Their demand was for adoption of pay-scales of the State Government. This is a Central Government undertaking, and its employees are asking that they should get the pay being received by the employees of the State Government's Agricultual Corporation. I would like to point out that the scale of the workers in this farm which is a unit of the Government of India, for the male workers is 65-3-80-400-510 plus DA and that for the female workers is 50-3-65-485-590 plus DA, while the State Government's sale of pay in force in July, 1988 in the Kerala Farms is 720-10-760-15-805-20-925-25-1000. It is a very lamentable situation that the Government of India undertaking is not able to give the pay-scales of the State Government. This is a very reasonable demand made by the workers.